

2019 में मारुति ने बेचीं नौ साल में सबसे कम कार

कमजोर आर्थिक वृद्धि व खपत घटने से बिक्री पर दबाव

शैली सेठ मोहिले मुंबई, 1 जनवरी

कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री में कैलेंडर वर्ष 2019 में सालाना आधार पर 12.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। बिक्री में गिरावट लगभग एक दशक में सबसे ज्यादा रही। कमजोर आर्थिक वृद्धि और खपत घटने से कंपनी की बिक्री पर दबाव पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.5 फीसदी की कमजोर दर से बढ़ी, जो 5 साल में सबसे कम थी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए वर्ष से मारुति को उम्मीद है, लेकिन वह बीएस-6 के क्रियान्वयन से पहले अगले कुछ महीनों में अनिश्चितताओं को लेकर सतर्क बनी हुई है।

व्लूमबर्ग के आंकड़े के अनुसार वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में बलेनो और ब्रेजा मॉडलों की बिक्री एक साल पहले के 18 लाख वाहनों से घटकर 16 लाख रह गई। 12 वर्ष में यह दूसरी बार है जब जापानी कार निर्माता की स्थानीय कंपनी ने अपनी बिक्री में गिरावट दर्ज की है। मारुति की बिक्री कैलेंडर वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती वर्ष के 12 लाख वाहनों की तुलना में 8.1 प्रतिशत घटकर 11 लाख वाहन रह गई।

मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, 'पिछला वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण था। भविष्य में सतर्क रहने और आशान्वित होने की वजह दिख रही हैं।' उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा कर्ज की दरों में कमी और ग्रामीण

मारुति सुजुकी को नए साल से उम्मीद



■कंपनी ने कहा, पिछला वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण था। भविष्य में सतर्क रहने और आशान्वित होने की वजह दिख रही हैं

■कंपनी का मानना है कि बैंकों द्वारा कर्ज की दरों में कमी और ग्रामीण बिक्री में सुधार सकारात्मक हैं

बिक्री में सुधार सकारात्मक हैं।

हालांकि वह इसे लकर सतर्क बने हुए हैं कि स्वाभित्व की लागत चालू वर्ष में ऊंचे स्तरों पर बने रहने की आशंका है। इससे दबाव पैदा हो सकता है। बीएस-6 से बिक्री में मजबूती आएगी। ब्रेजा और एस क्रॉस के पेट्रोल बीएस-6 वैरिएंट्स की पेशकश से भी मारुति की कुल बिक्री में मदद मिलेगी।

इस बीच, मारुति अप्रैल से डीजल कारों का उत्पादन बंद किए जाने के बाद पैदा हुई कमी की भरपाई के लिए सीएनजी मॉडलों पर दांव लगा रही है। कंपनी का मानना है कि यदि सरकार ऐसे वाहनों पर जीएसटी घटाती है तो सीएनजी मॉडलों की बिक्री में इजाफा हो सकता है।

श्रीवास्तव का कहना है कि कुछ

नीतिगत बदलावों, स्वाभित्व की लागत में वृद्धि, पथ कर में वृद्धि, नकदी संकट वाहनों पर जीएसटी दर में संभावित कमी की चर्चा ने खरीदारों को खरीदारी टालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर दबाव से भी चिंताओं में इजाफा हुआ।

रिलायंस सियोरिटीज ने विश्लेषक मितुल शाह ने कहा, 'इन सभी विपरीत कारकों ने 2019 में उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाला। जब तक बीएस-6 का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो जाता, तब तक कुछ शहीन का तका यह दबाव बना रहेगा।' महानों मानना है कि यात्री वाहन खंड में वित्त वर्ष 2021 से ही मजबूत वृद्धि देखेगी। उन्होंने मारुति की नई वाहन पेशकशों से भी बिक्री में सुधार आने की उम्मीद है।

हीरो इलेक्ट्रिक ने 700 करोड़ रुपये का निवेश टाला

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी 700 करोड़ रुपये की निवेश योजना को एक साल के लिए टाल दिया है।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि फेम-दो योजना वांछित नतीजे देने में विफल रही है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र नीचे आ रहा है। इस वजह से कंपनी को अपनी निवेश योजना को टालना पड़ा।

हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने कहा, कंपनी चाहती है कि इस नीति को पुनर्निर्दिित किया जाए। कंपनी चाहती है कि कम रफ्तार के दोपहिया को भी सब्सिडी के लिए शामिल किया जाना

चाहिए। उन्होंने दलील दी कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये लागत दक्ष वाहन महत्वपूर्ण हैं। मुंजाल ने कहा, 'उद्योग के दृष्टिकोण से फेम-एक में कुछ हो रहा था लेकिन फेम-दो के आने के बाद, चाहे कोई भी तर्क या वजह हो, जिस तरीके से फेम-दो लागू किया गया, उससे पूरा उद्योग नीचे आ गया। हालांकि अब उद्योग उससे उबर रहा है।'

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के संगठन एसएमईवी के फेम-दो के पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिज्री अप्रैल-दिसंबर, 2019 की अवधि में मात्र 3,000 इकाई रही है।

भाषा

सावधि ऋण में एसबीआई का प्रदर्शन बेहतर

पृष्ठ-1 का शेष

क्या आपको लगता है कि आईबीसी सफल रहा है?

एस्सार स्टील के फैसले के बाद मैं आईबीसी को लेकर बेहद संतुष्ट हूं। विदेशी निवेशक भी वापस आएंगे। हमने देखा है कि एस्सार स्टील में आर्सेलर मितल की तरफ से 42,000 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है। यह अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के

लिए सकारात्मक खबर है क्योंकि कंपनी में और निवेश आएगा। रतन इंडिया के मामले में भी विदेशी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। कई कंपनियों का समाधान हो रहा है। दिसंबर में ही चार कंपनियों एस्सार स्टील, रुचि सोया, प्रयागराज पावर और रतन इंडिया का समाधान हुआ है। जेपी इन्फोटेक का मामला भी मार्च तक सुलझने की संभावना है। इसके अलावा भूषण पावर एंड स्टील, आलोक इंडस्ट्रीज और

रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी समाधान हो सकता है। आईबीसी के तहत रिकॉर्ड संख्या में मामले दायर किए गए हैं।

क्या एनबीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता की चिंता दूर हो गई है? मुझे लगता है कि यह सही है। मुझे तत्काल किसी चूक या खतरे का अंदेशा नहीं है। यह सही है कि एनबीएफसी का रियल एस्टेट क्षेत्र में अच्छाखासा निवेश है। जो रियल

की जरूरत है। साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी होने के करीब हैं जिनके लिए सरकार ने रियल्टी फंड मुहैया कराया है।

क्या आप मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो से चिंतित हैं?

मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो हमारे लोन बुक का 1.1 फीसदी है। इस तरह अगर इस श्रेणी में 10 फीसदी एनपीए भी होगा तो इससे हम पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। डीएचएफएल जैसे खातों से हम पर असर पड़ेगा क्योंकि अचानक 10,000 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए बन जाएगा।

PRE-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF

FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

Registered Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F-79 & 80, Okhla Phase - I, New Delhi South Delhi 110020. Tel: +91 11 4905 7597 Fax: + 91 12 4429 2840, CIN: L74899DL1954PLC002452

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 1,39,16,676 (ONE CRORE THIRTY NINE LAKHS SIXTEEN THOUSAND SIX HUNDRED AND SEVENTY SIX) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH ("EQUITY SHARES"), FROM THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ("ELIGIBLE SHAREHOLDERS") OF FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED ("TARGET COMPANY") BY TENNECO INC. ("ACQUIRER") TOGETHER WITH ICAHN ENTERPRISES LP ("IEHP" OR "PAC 1"), AMERICAN ENTERTAINMENT PROPERTIES CORP. ("AEP" OR "PAC 2") AND IEH FMGI HOLDINGS LLC ("IEH" OR "PAC 3") (COLLECTIVELY KNOWN AS "PACs") IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(i), 4, 5(i) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS") AT A PRICE OF INR 667.50 PER EQUITY SHARE ("OFFER/OPEN OFFER").

This Pre-Offer Advertisement is being issued by CKP Financial Services Private Limited, the manager to the Offer ("Manager"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs in respect of the Offer to the Eligible Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Pre-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement dated April 16, 2018 ("PA"), the Detailed Public Statement dated October 9, 2018 ("DPS"), the Draft Letter of Offer dated October 16, 2018 ("DLoF"), Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019 ("Corrigendum 1"), Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 ("Corrigendum 2") and the Letter of Offer dated December 30, 2019 dispatched to the Eligible Shareholders of the Target Company ("LoF").

Capitalized terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the LoF, unless otherwise defined.

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Offer:

1. **Upward revision in the Offer Price:** In the DPS, an offer price of INR 420.05 (Indian Rupees Four Hundred Twenty and Paise Five Only) per Equity Share was offered, consisting of a base price of INR 400 (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share plus interest of INR 20.05 (Indian Rupees Twenty and Paise Five Only). However, SEBI's observation letters dated March 20, 2019 and July 4, 2019, directed revision of the base offer price upwards from INR 400 (Indian Rupees Four Hundred Only) to INR 608.46 (Indian Rupees Six Hundred Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share. Acquirer filed an appeal against the observation letters received from SEBI at the Honourable Securities Appellate Tribunal ("SAT") on April 1, 2019 and July 15, 2019 respectively. SAT passed its orders dated May 16, 2019 and November 7, 2019 respectively. SAT order dated November 7, 2019 was in favour of SEBI. Acquirer along with PACs lodged an appeal with the Honourable Supreme Court on December 3, 2019. The Honourable Supreme Court disposed the appeal on December 16, 2019 and upheld the offer price of INR 608.46 (Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share ("Offer Price").

In compliance with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price of INR 608.46/- (Indian Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share has been enhanced by INR 30.51/- (Indian Rupees Thirty and Paise Fifty One Only) per Equity Share, being the interest determined at the rate of 10 per cent per annum on the Offer Price for the period between the date of the Underlying Agreement (agreement triggering the Offer) i.e. April 10, 2018 and the date of publication of the DPS i.e. October 9, 2018. Further, as per the final SEBI observation letter dated July 4, 2019, the applicable tendering period would have been from July 22, 2019 to August 2, 2019 with the last date for payment of consideration being August 20, 2019. Subsequent to the SEBI observation letter dated July 4, 2019, legal remedies were pursued at the SAT and the Honourable Supreme Court, and the final order was pronounced by the Honourable Supreme Court on December 16, 2019, leading to a revision in the tendering period to January 6, 2020 to January 17, 2020 with last date for payment of consideration being January 31, 2020. Accordingly, the additional interest for the period between August 21, 2019 to January 30, 2020 is INR 28.53 (Indian Rupees Twenty Eight and Paise Fifty Three Only) per Equity Share. Thus the Enhanced Offer Price is INR 667.50 (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only).

2. Financial Arrangements:

2.1 Based on the Enhanced Offer Price, the maximum consideration payable under this Offer (assuming full acceptance) at the Enhanced Offer Price of INR 667.50 per Equity Share will be INR 928,93,81,230/- (Indian Rupees Nine Hundred and Twenty Eight Crore Ninety Three Lakh Eighty One Thousand Two Hundred and Thirty Only) i.e. the consideration payable for acquisition of 1,39,16,676 Equity Shares at the Enhanced Offer Price.

2.2 Pursuant to Regulation 17(2) of the SAST Regulations, in case of upward revision of the offer price, the value of the escrow account is required to be calculated for the revised offer price and the additional amount is required to be brought into the escrow account prior to effecting such revision. Accordingly, in light of revision of the Offer Price, PAC 3 has made an aggregate cash deposit of INR 167,96,70,000.37 (Indian Rupees One hundred and Sixty Seven crores Ninety Six lakhs Seventy Six thousand and Paise Thirty Seven Only) in the Open Offer Escrow Account ("Escrow Amount"), which is equal to the amount required to be deposited, computed basis the offer size, in accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. **Recommendation of the Committee of Independent Directors:** The committee of independent directors of the Target Company (the "IDC") has recommended that the shareholders should independently evaluate the offer. The recommendations of the IDC is published in the same newspapers in which the DPS was published. A summary of the relevant extracts of the IDC's recommendations are below:

Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. K. N. Subramaniam 2. Mr. Mukul Gupta Mr. K. N. Subramaniam is the Chairman of the Committee.
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The Honourable Supreme Court vide its order dated December 16, 2019 has upheld the valuation of shares at Rs. 608.46/- together with interest pursuant to the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations. The members of the IDC believe that the Open Offer made to the shareholders of Target Company at a price of Rs. 667.50/- (including interest component of Rs. 59.04) per fully paid Equity Share of Rs. 10/- each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the Public Announcement dated April 16, 2018, Detailed Public Statement (DPS) dated October 09, 2018, Draft Letter of Offer dated October 16, 2018, Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019, Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 and Letter of Offer dated December 30, 2019 including the Valuation Report dated April 03, 2019, provided by Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: - The Securities Exchange Board of India communication dated July 4, 2019, together with the Observation letter of SEBI. - The Order of the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, in Appeal nos. 352 and 359 of 2019, Appeal Lodging Nos. 458 and 459 of 2019 and Miscellaneous Application no. 418 of 2019, dated November 07, 2019. - The Order of the Supreme Court of India, in Civil Appeal nos. 9225/9226 of 2019 dated December 16, 2019. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.

- The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
- The Letter of Offer was dispatched to all Eligible Shareholders of the Target Company on December 30, 2019.
- Eligible Shareholders are required to refer section 7 "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 60 of the LoF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. Please note that a copy of the LoF (including Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (<http://www.sebi.gov.in>) during the Tendering Period and shareholders can also apply by downloading such forms from SEBI's website. Further, in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details:
 - Eligible Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the LoF, may participate in this Offer by:
 - downloading the LoF along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtaining a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares; or
 - submitting an application on a plain paper to their Selling Broker giving details regarding their shareholding and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in PA, the DPS and the LoF and submitting all the required documents as identified in the LoF.
 - In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the DLoF was submitted to SEBI on October 16, 2018. The final observations from SEBI were received in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations vide letter dated July 4, 2019, which have been incorporated in the LoF.

कंपनी समाचार 3



वसूली अधिकारी—। का कार्यालय

ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

ई—नीलामी

बिक्री सूचना

आर.सी. सं. 449/2018

मेरे आदेश दिनांकित 05-12-2019 के अनुसार उक्त वसूली प्रमाणपत्र में निम्नवर्णित सम्पत्ति दिनांक 22-01-2020 को सार्वजनिक ई—नीलामी द्वारा बेची जाएगी।—

नीलामी बिक्री वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> के माध्यम से "ऑनलाइन ई—नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समय : 22-01-2020 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच (दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तारों सहित, यदि अपेक्षित है)।

केंनरा बैंक बनाम श्री सतेन्द्र कुमार जैन

दिनांकित : 05-12-2019

सम्पत्ति का वर्णन

गिरवी रखी हुई संपत्ति अर्थात प्लॉट नं 18/14, मापक्षेत्र 744.27 वर्ग मीटर साइट—IV, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201011

आरक्षित मूल्य: रु. 2,76,00,000 /—(रुपए दो करोड़ छहतर लाख मात्र)

घरौहर जमा राशि (EMD): रु. 27.60,000 /— (रुपए सत्ताईस लाख साठ हजार मात्र)

नियम और शर्तें

- नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल: www.bankauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई—नीलामी" होगी।
- ईएमडी "वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली खाता आर/सी सं. 449/2018" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण, पहचान पत्र (निर्वाचन आई कार्ड)/झड़िये लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें आगे संचार/पत्रव्यवहार के लिए पता होना चाहिए, की स्व-सत्यापित प्रति तथा पेन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 21-01-2020 अपराह्न 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के भुगतान के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ईएमडी अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण सन्निहित लिफाफे पर "आरसी सं. 449/2018" तथा प्रेषक का विवरण अर्थात पता, ई—मेल आईडी और मोबाइल नम्बर इत्यादि शीर्षकित किया जाना चाहिए।
- सम्पत्ति की बिक्री "जैसी है जहां है" आधार" पर की जा रही है।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली देने तथा ई—नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल www.bankauctions.com अच्छी तरह पढ़ लें तथा/अथवा श्री रमेश, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबा: 8527462333, दूरभाष: 011-22373900 से सम्पर्क करें।
- भागी बोलीदाताओं से पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना तथा मैसर्स सी। इंडिया प्रा. लिमिटेड, गल्फ पेद्रो केमिकल प्लॉट नंबर 301, पहली मंजिल, उद्योग विहार फेज—।।, मुडगांव (हरियाणा) दूरभाष नं. 91-124-4302020/21/22/23/24, ई—7210044289, +91-9813887931 से लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, जो उपरोक्त ई—नीलामी में बोलीदाक के लिए अनिवार्य है।
- इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी। इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-104, सेक्टर-22, नोएडा—201301, यू.पी., फोन नं. : 0120 4746800, मोबा: 09810029923, संपर्क व्यक्ति: किशोर्द चौधान, मोबा. नं. 09813887931, ई—मेल आईडी: support@bankauctions.com से ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- केवल वे बोलीदाता ऑनलाइन ई—नीलामी में भाग लेने हेतु मान्य होंगे जो बैंच यूजर आईडी एवं पासवर्ड और डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान पद्धि के धारक हैं।
- इच्छुक बोलीदाता जो 21-01-2020 से पूर्व अपनी बोलियां, जो सुरक्षित मूल्य से कम नहीं है, वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली के कार्यालय में जमा कर चुके होंगे, ई—नीलामी में भाग लेने हेतु उपयुक्त होंगे जो 22-01-2020 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। नीलामी समाप्त होने के आखिरी 5 मिनट में कोई बोली आने पर नीलामी समाप्त होने का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
- बोलीदाता संबंधित सम्पत्ति हेतु अपनी बोली रु. 1,00,000 /— (रु. एक लाख मात्र) के गुणज में बढ़ाएंगे।
- असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी ई—नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल परश्चात सीधे वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली/सीएच, नामतः केनरा बैंक से प्राप्त कर सकेंगे।
- सफल/उच्चतम बोलीदाता को बोली/बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 449/2018 के पक्ष में ई—नीलामी के समापन के बाद के 24 घंटे के भीतर और ईएमडी को समाप्त होने के बाद और इस मूल्य को वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली के कार्यालय में भेजें/जमा करें, इसीलिए ई—नीलामी के समापन होने के बाद से 3 दिनों के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा, ईएमडी को जप्त कर लिया जाएगा।
- सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 449/2018 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली के पास सम्पत्ति की ई—नीलामी बिक्री के 15वें दिन अथवा पूर्व, उस तिथि को छोड़कर, और 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्या दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी—।।, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000 /— तक 2 प्रतिशत निरोध शुल्क तथा रु. 1000 /— से ऊपर सकल राशि पर 1 प्रतिशत निरोध शुल्क के साथ जमा करनी होगी। (शेष 75 प्रतिशत राशि आक द्वारा जमा करने की स्थिति में यह वसूली अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्राप्त हो जानी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा के बाद, अधिकारी की बिक्री दोबारा की जाएगी। चूककर्ता क्रेता द्वारा जमा की गई राशि, बिक्री संबंधी खर्चे काटकर, यदि अवशेषरक्ताई द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार को जाने में जब्त कर की जाएगी तथा सम्पत्ति या उसके किसी अंश की अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे जप्त माने जाएंगे।
- अवशेषरक्ताई के पास किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य नहीं पाई जाती है, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी प्रारंथित करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम मान्य होगा।।

सम्पत्ति की अनुसूची

बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
गिरवी रखी हुई संपत्ति अर्थात प्लॉट नं 18/14, मापक्षेत्र 744.27 वर्ग मीटर साइट—IV, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201011				

(अविनाश चन्द)

अतिरिक्त प्रमाण

वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली

परमाणु परीक्षणों पर लगी रोक हटाई उत्तर कोरिया ने

सोल, 1 जनवरी (एएफपी)।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षाों पर लगी रोक हटाने का एलान किया और जल्द नए सामरिक हथियार के प्रदर्शन की धमकी दी है।

विश्लेशकों का कहना है कि सरकारी मीडिया की यह खबर ऐसी है, मानो किम डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर मिसाइल रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के उकसावे पर उत्तर कोरिया को भी जवाब मिलेगा। अमेरिका इसका जवाब देने के लिए तत्पर है, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किम को ‘कोई और रास्ता अपनाने’ की सलाह देते हुए कहा कि उनका देश उत्तर कोरिया के साथ शांति चाहता है न कि विवाद। बहरहाल, ट्रंप ने इस घटनाक्रम को वूल नहीं दिया। उत्तर कोरिया इससे पहले समूचे अमेरिकी भू-भाग को जद में लेने में सक्षम मिसाइलों का परीक्षण और छह परमाणु परीक्षण कर चुका है। इनमें से आखिरी परीक्षण की क्षमता हिरोशिमा विस्फोट से भी 16 गुना अधिक शक्तिशाली थी। कोई भी वास्तविक परीक्षण ट्रंप के कोप को बढ़ाने वाला होगा जो अक्सर किम पर अपना ‘बादा नहीं निभाते’ का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कम दूरी वाले हथियारों के परीक्षण को कोई तवज्जो नहीं दी।

दोनों देशों के नेताओं के बीच फरवरी में हनोई शिखर वार्ता बेनतीया रहने के बाद से वार्ता में गतिविध बना हुआ है और उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों पर राहत की ताजा पेशकश देने के लिए अमेरिका को साल के अंत तक की समयसीमा दी थी। सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने किम के हवाले से कहा, ‘हमारे लिए अब एकतरफा प्रतिबद्धता को निभाते रहने का कोई आधार नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘दुनिया एक नया सामरिक हथियार देखेगी जो निकट भविष्य में उत्तर कोरिया के पास होगा।’

किम ने पार्टी के अधिकारियों को स्पष्ट किया कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता की रक्षा करेगा भले

पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों की सूची सौंपी

इस्लामाबाद, 1 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान ने देश की जेल में बंद 55 नागरिकों और 227 मछुआरों समेत 282 भारतीय कैदियों की एक सूची द्विपक्षीय समझौते के तहत बुधवार को भारतीय उच्चायोग की सौंपी। विदेश कार्यालय ने बताया कि यह

ही इसके लिए उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। केसीएनए ने किम के हवाले से कहा, ‘अमेरिका ऐसी मांगे कर रहा है जो हमारे देश के मौलिक हितों के विपरीत है और किसी लुटेरे की तरह व्यवहार कर रहा है।’ उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने कई बड़े और छोटे संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जिसे रोकने का उसके राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से वादा किया था और उसने दक्षिण कोरिया में उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण भेजे तथा उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ा दिए।

उन्होंने कहा, ‘हम कभी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकते। हमारे लोगों को हुई तकलीफ की भरपाई करने के लिए प्योंगयांग हैरतअंजेज कदम उठाएगा।’ अमेरिका में सेंटर फॉर द नेशनल इंटररेस्ट के हैरी काजियानिस ने कहा, ‘उत्तर कोरिया जो दो रियायतें प्रतिबंध में ढील और सुरक्षा की गारंटी चाहता है, उसे हासिल करने के बजाय मानो वह ट्रंप के सिर पर मिसाइल रखने का प्रयास कर रहा है।’ उन्होंने कहा कि यह रणनीति जोखिम भरा है क्योंकि इसके जवाब में ‘अमेरिका के और अधिक ‘प्रतिबंध’ लगाने, पूर्वी एशिया में सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने तथा डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से धमकी भरे ट्वीट आने की संभावना है।’ सोल में एवहा यूनिवर्सिटी के लीफ-एरिक इंजली ने कहा कि किम की यह टिप्पणी ‘घातक’ है।

वहीं, अमेरिका ने पहले ही संकेत दिए हैं कि अगर उत्तर कोरिया लंबी दूरी का मिसाइल परीक्षण करता है तो वह उसका जवाब देगा। किम की इस घोषणा के बाद ‘फॉक्स न्यूज’ और ‘सीबीएस’ को पोम्पियो ने कहा, ‘परमाणु एवं मिसाइल परीक्षण की बहाली बेहद निराशाजनक है।’ उन्होंने कहा, ‘आशा करता हूं कि किम अलग मार्ग अपनाएंगे और विवाद एवं युद्ध की जगह शांति एवं समृद्धि का चुनेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हम लोग शांति चाहते हैं, विवाद नहीं।’ सोल के यूनिफिकेशन मंत्रालय ने कहा कि सामरिक हथियार के परीक्षण से ‘परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत’ में मदद नहीं मिलेगी।

दुनिया

ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, पर युद्ध से इनकार

वाशिंगटन, 1 जनवरी (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध का विचार ठीक नहीं है, हालांकि उन्होंने बग़दाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले को लेकर चेतावनी दी है। इराकी शिया मिलिशिया समर्थकों (जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं) ने मंगलवार को अमेरिकी दूतावास परिसर की दीवार को तोड़ दिया था। उन्होंने परिसर के स्वागत क्षेत्र में आग लगा दी थी।

प्रदर्शनकारी रविवार को हुए अमेरिकी हवाई हमलों का विरोध कर रहे थे, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह (हिजबुल्ला ब्रिगेड) के कट्टरपंथी गुट के कम से कम 25 लड़ाके मारे गए थे। अमेरिका ने इस गुट पर अमेरिकी ठेकेदार की हत्या का

आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ईरान में हालात से बेहतर ढंग से निपटा गया। ईरान के साथ युद्ध की आशंका के बारे में पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ईरान के लिए ये अच्छा विचार होगा... मैं शांति चाहता हूं... मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा।’ इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, ‘हमारे किसी भी प्रतिष्ठान में किसी की भी जान जाने या किसी भी प्रकार की क्षति के लिए ईरान पूरी ही तरह जिम्मेदार होगा।’ ट्रंप ने कहा, ‘उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह धमकी नहीं है, खतरा है। नववर्ष सुबारक हो।’ रक्षा मंत्री मार्क एस्पेर ने मंगलवार को कहा था कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की त्वरित प्रतिक्रिया इकाई के करीब 750 सैनिकों को अगले कुछ दिनों में भेजने की तैयारी है।

गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर गैर सिखों को करतारपुर गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं लाहौर, 1 जनवरी (भाषा)।

करतारपुर स्थित ऐतिहासिक दरबार साहिब गुरुद्वारे को पाकिस्तान गुरु गोबिंद सिंह जयंती समारोह पर स्थानीय गैर सिखों के लिए शुक्रवार से तीन दिन के लिए बंद रखेगा। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत में पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिला स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह जयंती समारोह पर तीन से पांच जनवरी तक पाकिस्तानी गैर सिखों को करतारपुर साहिब में प्रवेश न देने का निर्णय किया है।

PRE-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED Registered Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F-79 & 80, Okhla Phase - I, New Delhi South Delhi 110020. Tel: +91 11 4905 7597 Fax: + 91 12 4429 2840, CIN: L74899DL1954PLC002452
--

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 1,39,16,676 (ONE CRORE THIRTY NINE LAKHS SIXTEEN THOUSAND SIX HUNDRED AND SEVENTY SIX) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH ("EQUITY SHARES"), FROM THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ("ELIGIBLE SHAREHOLDERS") OF FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED ("TARGET COMPANY") BY TENNECO INC. ("ACQUIRER") TOGETHER WITH ICAHN ENTERPRISES LP ("IEP" OR "PAC 1"), AMERICAN ENTERTAINMENT PROPERTIES CORP. ("AEP" OR "PAC 2") AND IEH FMGI HOLDINGS LLC ("IEH" OR "PAC 3") (COLLECTIVELY KNOWN AS "PACS") IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1), 4, 5(1) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS") AT A PRICE OF INR 667.50 PER EQUITY SHARE ("OFFER/OPEN OFFER")

This Pre-Offer Advertisement is being issued by CKP Financial Services Private Limited, the manager to the Offer ("Manager"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs in respect of the Offer to the Eligible Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Pre-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement dated April 16, 2018 ("PA"), the Detailed Public Statement dated October 9, 2018 ("DPS"), the Draft Letter of Offer dated October 16, 2018 ("DLoF"), Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019 ("Corrigendum 1"), Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 ("Corrigendum 2") and the Letter of Offer dated December 30, 2019 dispatched to the Eligible Shareholders of the Target Company ("LoF").

Capitalized terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the LoF, unless otherwise defined.

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Offer:

- Upward revision in the Offer Price:** In the DPS, an offer price of INR 420.05 (Indian Rupees Four Hundred Twenty and Paise Five Only) per Equity Share was offered, consisting of a base price of INR 400 (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share plus interest of INR 20.05 (Indian Rupees Twenty and Paise Five Only). However, SEBI's observation letters dated March 20, 2019 and July 4, 2019, directed revision of the base offer price upwards from INR 400 (Indian Rupees Four Hundred Only) to INR 608.46 (Indian Rupees Six Hundred Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share. Acquirer filed an appeal against the observation letters received from SEBI at the Honourable Securities Appellate Tribunal ("SAT") on April 1, 2019 and July 15, 2019 respectively. SAT passed its orders dated May 16, 2019 and November 7, 2019 respectively. SAT order dated November 7, 2019 was in favour of SEBI. Acquirer along with PACs lodged an appeal with the Honourable Supreme Court on December 3, 2019. The Honourable Supreme Court disposed the appeal on December 16, 2019 and upheld the offer price of INR 608.46 (Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share ("Offer Price").

In compliance with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price of INR 608.46/- (Indian Rupees Six Hundred and Eight and Paise Forty Six Only) per Equity Share has been enhanced by INR 30.51/- (Indian Rupees Thirty and Paise Fifty One Only) per Equity Share, being the interest determined at the rate of 10 per cent per annum on the Offer Price for the period between the date of the Underlying Agreement (agreement triggering the Offer) i.e. April 10, 2018 and the date of publication of the DPS i.e. October 9, 2018. Further, as per the final SEBI observation letter dated July 4, 2019, the applicable tendering period would have been from July 22, 2019 to August 2, 2019 with the last date for payment of consideration being August 20, 2019. Subsequent to the SEBI observation letter dated July 4, 2019, legal remedies were pursued at the SAT and the Honourable Supreme Court, and the final order was pronounced by the Honourable Supreme Court on December 16, 2019, leading to a revision in the tendering period to January 6, 2020 to January 17, 2020 with last date for payment of consideration being January 31, 2020. Accordingly, the additional interest for the period between August 21, 2019 to January 30, 2020 is INR 28.53 (Indian Rupees Twenty Eight and Paise Fifty Three Only) per Equity Share. Thus the Enhanced Offer Price is INR 667.50 (Indian Rupees Six Hundred and Sixty Seven and Paise Fifty Only).

- Financial Arrangements:**
 - Based on the Enhanced Offer Price, the maximum consideration payable under this Offer (assuming full acceptance) at the Enhanced Offer Price of INR 667.50 per Equity Share will be INR 928,93,81,230/- (Indian Rupees Nine Hundred and Twenty Eight Crore Ninety Three Lakh Eighty One Thousand Two Hundred and Thirty Only) i.e. the consideration payable for acquisition of 1,39,16,676 Equity Shares at the Enhanced Offer Price.
 - Pursuant to Regulation 17(2) of the SAST Regulations, in case of upward revision of the offer price, the value of the escrow account is required to be calculated for the revised offer price and the additional amount is required to be brought into the escrow account prior to effecting such revision. Accordingly, in light of revision of the Offer Price, PAC 3 has made an aggregate cash deposit of INR 167,96,76,000.37 (Indian Rupees One hundred and Sixty Seven crores Ninety Six lakhs Seventy Six thousand and Paise Thirty Seven Only) in the Open Offer Escrow Account ("**Escrow Amount**"), which is equal to the amount required to be deposited, computed basis the offer size, in accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

- Recommendation of the Committee of Independent Directors:** The committee of independent directors of the Target Company (the "IDC") has recommended that the shareholders should independently evaluate the offer. The recommendations of the IDC is published in the same newspapers in which the DPS was published. A summary of the relevant extracts of the IDC's recommendations are below:

Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. K. N. Subramaniam 2. Mr. Mukul Gupta Mr. K. N. Subramaniam is the Chairman of the Committee.
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The Honourable Supreme Court vide its order dated December 16, 2019 has upheld the valuation of shares at Rs. 608.46/- together with interest pursuant to the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations. The members of the IDC believe that the Open Offer made to the shareholders of Target Company at a price of Rs. 667.50/- (including interest component of Rs. 59.04) per fully paid Equity Share of Rs. 10/- each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the Public Announcement dated April 16, 2018, Drafted Public Statement (DPS) dated October 09, 2018, Detail Letter of Offer dated October 16, 2018, Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019, Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 and Letter of Offer dated December 30, 2019 including the Valuation Report dated April 03, 2019, provided by Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: - The Securities Exchange Board of India communication dated July 4, 2019, together with the Observation letter of SEBI. - The Order of the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, in Appeal nos. 352 and 359 of 2019, Appeal Lodging Nos. 458 and 459 of 2019 and Miscellaneous Application no. 418 of 2019, dated November 07, 2019. - The Order of the Supreme Court of India, in Civil Appeal nos. 9225/9226 of 2019 dated December 16, 2019. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.

- The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
- The Letter of Offer was dispatched to all Eligible Shareholders of the Target Company on December 30, 2019.
- Eligible Shareholders are required to refer section 7 "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 60 of the LoF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. Please note that a copy of the LoF (including Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (<http://www.sebi.gov.in>) during the Tendering Period and shareholders can also apply by downloading such forms from SEBI's website. Further, in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details:
 - Eligible Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the LoF, may participate in this Offer by:
 - downloading the LoF along with the Form of Acceptance-cum- Acknowledgment from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtaining a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares; or
 - submitting an application on a plain paper by their Selling Broker giving details regarding their shareholding and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in PA, the DPS and the LoF and submitting all the required documents as identified in the LoF.
- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the DLoF was submitted to SEBI on October 16, 2018. The final observations from SEBI were received in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations vide letter dated July 4, 2019, which have been incorporated in the LoF.

- Details regarding the status of the statutory and other approvals:** As disclosed in the LoF, to the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, all the statutory approvals required by the Acquirer or the PACs to complete this Offer have been obtained. However, in case of any additional statutory approvals being required by the Acquirer or the PACs at any later date, this Offer will be subject to such approvals. In the event that any statutory approvals required are not obtained or are finally refused or are otherwise not received for reasons outside the reasonable control of the Acquirer and/or PACs, the Acquirer and/or PACs may withdraw the Offer under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. Non-resident Indian ("NRI") and overseas corporate body ("OCB") holders of the Equity Shares, must obtain all approvals required to tender the Equity Shares held by them in this Offer (including without limitation, an approval from the Reserve Bank of India ("RBI") and submit such approvals along with the Form of Acceptance cum - Acknowledgement and other documents required under this Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India including NRIs, OCBs, FIs and FPIs had required any approvals (including from the RBI or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals that they would have obtained for holding the Equity Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event that such approvals are not submitted, the Acquirer and PACs shall reject any such Equity Shares tendered in this Offer.

- The revised schedule of activities pertaining to the Offer is set out below:

Activity	Day and Date	
	Original	Revised
PA Date	Monday, 16 April 2018	Monday, 16 April 2018
Date of publication of the DPS	Tuesday, October 9, 2018	Tuesday, October 9, 2018
Date by which DLoF is to be filed with the SEBI	Tuesday, October 16, 2018	Tuesday, October 16, 2018
Last date for a competing offer (within 15 (fifteen) Working Days of the DPS)	Wednesday, October 31, 2018	Wednesday, October 31, 2018
Last date for SEBI observations on the DLoF (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Friday, November 9, 2018	Wednesday, March 20, 2019
Appeal 1 filed by Acquirer with SAT	-	Monday, April 1, 2019
SAT Order/Decision for the Appeal 1	-	Thursday, May 16, 2019
SEBI Observations on the DLoF – upholding the revised offer price	-	Thursday, July 4, 2019
Appeal 2 filed by Acquirer with SAT	-	Monday, July 15, 2019
SAT Order/Decision for the Appeal 2	-	Thursday, November 7, 2019
Appeal 3 filed by the Acquirer with the Supreme Court	-	Tuesday, December 3, 2019
Supreme Court Order	-	Monday, December 16, 2019
Identified Date*	Tuesday, November 13, 2018	Friday, December 20, 2019
Last date by which Letter of Offer ("LoF") will be dispatched to the Eligible Shareholders	Tuesday, November 20, 2018	Monday, December 30, 2019
Last date by which the committee of independent directors constituted by the Board of Directors of the Target Company shall give its recommendation (up to 2 (two) working days prior to the commencement of the Tendering Period)	Monday, November 26, 2018	Wednesday, January 1, 2020
*"Last date for the revision of the Offer Price/number of Equity Shares (Prior to the commencement of last 1 (one) Working Day before the commencement of the Tendering Period)	Thursday, November 22, 2018	Thursday, January 2, 2020
Date of Advertisement announcing the schedule of activities for the open offer, status of statutory and other approvals, status of unfulfilled conditions (if any), etc. in the newspapers in which the DPS has been published	Wednesday, November 28, 2018	Thursday, January 2, 2020
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Thursday, November 29, 2018	Monday, January 6, 2020
Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Wednesday, December 12, 2018	Friday, January 17, 2020
Last date of communicating the acceptance/ rejection and payment of consideration (net of applicable taxes) or refund of Equity Shares under the Offer to the Eligible Shareholders	Thursday, December 27, 2018	Friday, January 31, 2020
Last date for publication of post-offer public announcement in the newspapers in which the DPS had been published	Thursday, January 3, 2019	Friday, February 7, 2020

"Date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of the Tendering Period. The Identified Date is only for the purpose of determining the Eligible Shareholders as on such date to whom this Letter of Offer would be sent. All the Eligible Shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares of the Target Company are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Tendering Period.

***change in SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018, w.e.f. 11-09-2018, prior to this, it was "three working days".*

- The Acquirer and PACs accept full responsibility for the information contained in this Pre-offer advertisement and also the obligations of the Acquirer and PACs as laid down in the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments thereof.

- This Advertisement is expected to be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

FOR THE ATTENTION OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS

SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time, has provided guidelines on the mechanism for acquisition of shares through the stock exchange pursuant to, inter alia, tender-offers under SEBI (SAST) Regulations, to facilitate tendering of shares by the shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism. In accordance with these circulars and notices/guidelines issued by the Stock Exchanges and Clearing Corporation in relation to the mechanism of acquisition of shares, this Offer is being carried out through the stock exchange mechanism (in the form of a separate acquisition window provided by BSE Limited, being the designated stock exchange), and hence would be subject to payment of securities transaction tax. For further details, Eligible Shareholders are requested to refer to section 7 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 60 of the LoF.

As per the provisions of regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019. Accordingly, the Eligible Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialised. Such Eligible Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialised.

MANAGER TO THE OFFER			
 CKP FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Delsol, 1st floor, CTS No. C/597 & C/598, D'Monte Park Road, Near Bandra Gymkhana, Bandra (West), Mumbai-400050, India Tel: +91-9322997964 E-mail: fmgi.openoffer@ckpfinancialservices.com Contact Person: Mr. Brijesh Parekh			
Issued for and on behalf of the Acquirer and PACs			
Acquirer	PAC 1	PAC 2	PAC 3
Tenneco Inc. 3411 Silverside Road, Tathnall Building #104, Wilmington, DE 19810/ 500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, United States of America	Icahn Enterprises LP 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America.	American Entertainment Properties Corp. 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America.	IEH FMGI Holdings LLC 767 5th Avenue, New York, NY 10153, United States of America.

Place: Mumbai

Date: January 01, 2020